VAID ICS LUCKNOW

 **Daily Answer Writing Programme ( DAWP)**

**Resources:** The Hindu/ Indian Express/ BS/ET/Down to Earth

**Date : 14 May 2024**

**Qn.1** India need to redesign its development strategy to bring more equitable growth & Job creation. Discuss 250 words

भारत को अधिक न्यायसंगत विकास और रोजगार सृजन लाने के लिए अपनी विकास रणनीति को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है। चर्चा करें।

The equitable growth refers to an equitable distribution of national income so that the benefits of higher economic growth can be passed on to all sections of the population to bring about social justice.

Job creation refers to the process of providing new jobs, especially for people who were previously unemployed or inactive.

 After brief intro give some facts about income inequality and job creation:

Eg - In 2022-23, the average income of the **top 1% in India was approximately Rs 53 lakh per** year, which is **23 times more than the average income of Rs 2.3 lakh** for the rest of the population.

The Youth unemployment was around 14% in 2022-23.

**Challenges:**

**Focus on GDP growth:** The current strategy often prioritizes high GDP growth, which may not translate into widespread prosperity. Benefits can concentrate in specific sectors or regions, leaving others behind.

**Skill mismatch:** The education system might not be equipping youth with the skills required by the job market. This leads to unemployment despite a growing economy.

**Informal sector:** A large portion of the workforce is in the informal sector, with low wages and limited social security.

**Rural-urban divide:** Development is often concentrated in urban areas, neglecting rural infrastructure and agricultural productivity, hindering job creation in these regions.

 **Steps taken :**

 **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):** It provides financial inclusion to unbanked citizens, particularly in rural areas, by opening bank accounts and offering financial services.

**Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan):** It provides income support to small and marginal farmers

 **Skill India Mission:** This initiative aims to train youth in job-relevant skills to bridge the skill gap and enhance employability.

 **Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):** Launched in 2015, this scheme provides loans to micro and small enterprises (MSMEs) to support entrepreneurship and job creation.

 **Start-up India Initiative:** This program aims to create a vibrant startup ecosystem in India by offering tax benefits, incubation facilities, and mentorship to entrepreneurs.

**Stand Up India:** Launched in 2015, this scheme encourages banks to provide loans to women entrepreneurs from Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs).

**Stand Up Mitran Scheme:** This scheme aims to create a network of women entrepreneurs across the country to facilitate financial inclusion and provide support to other women entrepreneurs

**Designing a new approach:**

* Stimulate the growth of private consumption & private investment:
* Progressive taxation
* Substantial improvement in education & health sector
* Focus on inclusive growth:
* Skill development:
* Formalization of the informal sector
* **Rural development:** Invest in rural infrastructure, agricultural research, and extension services. Promote rural industries and entrepreneurship to create job opportunities outside urban centers.
* **Social safety nets:** Strengthen social safety net programs like MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) to provide a safety net for vulnerable populations during economic downturns.
* **Technological advancements:** Focus on leveraging technology for skilling, better market access for farmers, and promoting innovation in agriculture and rural industries.

**Decentralization:** Empower local governments to address regional needs and create development plans tailored to their specific contexts.

**Entrepreneurship:** Encourage entrepreneurship through business incubation centers, easier access to credit, and a supportive regulatory environment.

**Conclusion :**

Thus , a multi-pronged approach that addresses skill development, rural development, and promotes inclusive growth is crucial for India to achieve the goal of $5 trillion economy & equitable job creation and prosperity for all its citizens**.**

भारत को अधिक न्यायसंगत विकास और रोजगार सृजन लाने के लिए अपनी विकास रणनीति को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है। चर्चा करें।

समान विकास का तात्पर्य राष्ट्रीय आय के समान वितरण से है ताकि सामाजिक न्याय लाने के लिए उच्च आर्थिक विकास का लाभ आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सके।

नौकरी सृजन से तात्पर्य नई नौकरियाँ प्रदान करने की प्रक्रिया से है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पहले बेरोजगार या निष्क्रिय थे।

संक्षिप्त परिचय के बाद आय असमानता और रोजगार सृजन के बारे में कुछ तथ्य दें:

उदाहरण के लिए - 2022-23 में, भारत में शीर्ष 1% की औसत आय लगभग 53 लाख रुपये प्रति वर्ष थी, जो बाकी आबादी की औसत आय 2.3 लाख रुपये से 23 गुना अधिक है। 2022-23 में युवा बेरोजगारी लगभग 14% थी।

**चुनौतियाँ:**

**जीडीपी वृद्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता** : वर्तमान रणनीति अक्सर उच्च जीडीपी वृद्धि को प्राथमिकता देती है, जो व्यापक समृद्धि में तब्दील नहीं हो सकती है। लाभ विशिष्ट क्षेत्रों या क्षेत्रों में केंद्रित हो सकते हैं, दूसरों को पीछे छोड़ सकते हैं।

असमान कौशल शिक्षा प्रणाली युवाओं को नौकरी बाजार के लिए आवश्यक कौशल से लैस नहीं कर पा रही है। इससे बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद बेरोजगारी बढ़ती है।

**अनौपचारिक क्षेत्र**: कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहां कम वेतन और सीमित सामाजिक सुरक्षा है।

**ग्रामीण-शहरी विभाजन:** विकास अक्सर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होता है, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि उत्पादकता की उपेक्षा होती है, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन में बाधा आती है।

 **उठाए गए कदम:**

 **प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):** यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खाते से वंचित नागरिकों को बैंक खाते खोलकर और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन प्रदान करती है।

**प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान):** यह छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करती है

 **कौशल भारत मिशन**: इस पहल का उद्देश्य कौशल अंतर को पाटने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए युवाओं को नौकरी-प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षित करना है।

 **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):** 2015 में शुरू की गई, यह योजना उद्यमिता और रोजगार सृजन का समर्थन करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण प्रदान करती है।

 **स्टार्ट-अप इंडिया पहल:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमियों को कर लाभ, ऊष्मायन सुविधाएं और सलाह प्रदान करके भारत में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

**स्टैंड अप इंडिया:** 2015 में शुरू की गई यह योजना बैंकों को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

**स्टैंड अप मित्रन योजना:** इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने और अन्य महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में महिला उद्यमियों का एक नेटवर्क बनाना है।

* एक नया दृष्टिकोण डिजाइन करना:
* निजी उपभोग और निजी निवेश की वृद्धि को प्रोत्साहित करें:

प्रगतिशील कराधान

शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सुधार

समावेशी विकास पर ध्यान **देने की आवश्यकता**:

**कौशल विकास:**

**अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारिकीकरण**

**ग्रामीण विकास:** ग्रामीण बुनियादी ढांचे, कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में निवेश करें। शहरी केंद्रों के बाहर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देना।

**सामाजिक सुरक्षा जाल:** आर्थिक मंदी के दौरान कमजोर आबादी के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) जैसे सामाजिक सुरक्षा जाल कार्यक्रमों को मजबूत करें।

तकनीकी प्रगति: कौशल के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, किसानों के लिए बेहतर बाजार पहुंच और कृषि और ग्रामीण उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें।

**विकेंद्रीकरण:** स्थानीय सरकारों को क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने और उनके विशिष्ट संदर्भों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने के लिए सशक्त बनाना।

**उद्यमिता**: बिजनेस इनक्यूबेशन केंद्रों, ऋण तक आसान पहुंच और एक सहायक नियामक वातावरण के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करें।

**निष्कर्ष :**

 इस प्रकार, एक बहु-आयामी दृष्टिकोण जो कौशल विकास, ग्रामीण विकास को संबोधित करता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, भारत के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और अपने सभी नागरिकों के लिए समान रोजगार सृजन और समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।